केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की धांधली...

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बर्बाद कर रहा है साक्षर भारत कार्यक्रम को

आईएएस अफसर रीना राय उसके इस मिशन में शामिल है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: भारत के लोगों को पढ़ा-लिखा बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम साक्षर भारत को किस तरह उसका ही एक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और आईएएस अधिकारी रीना राय बर्बाद कर रहे हैं, इसका मामला हाल ही में उजागर हुआ है। देश अलग-अलग राज्यों में साक्षर भारत के तहत स्थापित 32 राज्य संसाधन केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा 25 करोड़ रूपये वार्षिक अनुदान दिया जाता है। परन्तु देश को साक्षर बनाने के लिए घोषित नई योजना में राज्य संसाधन केन्द्रों की भूमिका को खत्म कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और उनके मंत्रालय की स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव सुश्री रीना राय की जुगलबंदी ने देश के 32 राज्य संसाधन केन्द्रों पर ताला लटकाते हुए प्रौढ़ मनोविज्ञान पर काम करने वाले बेहतर संस्थानों का भट्ठा बैठा दिया है।

आईएएस अधिकारी रीना राय कुछ समय के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की महानिदेशक बनी थीं1 बहुत ही हैरानी की बात है कि साक्षर भारत का बंटाधार करने वाली यह प्रकाश जावडेकर की मुंह लगी अधिकारी अपनी पदोन्नति के बाद भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ही जमीं हुई हैं। आमतौर पर पदोन्नति पाने वाले अधिकारी का विभाग बदल जाता है। इन्हीं मोहतरमा की शह पर 1 अप्रैल 2018 से राज्य संसाधन केन्द्रों की आर्थिक मदद बंद कर दी है। यह न केवल एक कुशल मानव संसाधन की क्षति है बल्कि इससे देश को पूर्ण साक्षर बनाने की भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना की गति भी बाधित होगी। अभी 26 फरवरी को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की कारगुजारी के खिलाफ दिल्ली में बड़ा धरना प्रदर्शन भी हुआ।

अच्छे अधिकारी को हटाया

2017 में कुछ समय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में महानिदेशक के पद पर आईएएस अधिकारी अजय टिर्की आए थे। उन्होंने राज्य संसाधन केन्द्रों की भूमिका को सराहते हुए इनकी भूमिका को बढ़ाने और आर्थिक मदद बढ़ाने की कोशिश की। वे अपने योजना में कामयाब हो पाते रीना राय की लाबी ने उनका तबादला महिला एवं बाल विकास विभाग में करवा दिया।

दूसरी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल एवं साक्षरता विभाग ने 28-1-2019 को पत्र क्रमांक 2-3/2019-एन.एल.एम.3 के तहत सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी दी है कि राज्य संसाधन केन्द्रों का मूल्यांकन 1.3.2012 से 25-12-2018 तक 2 बार किया गया हैं। वर्ष 2013 में राज्य संसाधन केन्द्रों का मूल्यांकन आईआईएम लखनऊ द्वारा किया गया था। 2017 में मूल्यांकन सेंटर फार मार्केट रिसर्च एण्ड सोशल डेवलपमेंट द्वारा किया गया। राज्य संसाधन केन्द्रों का मूल्यांकन वित मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं 24(35)/ पीएफ-11/2012 दिनांक 5-8-2016 के तहत किया गया।

मूल्यांकन करने वाली संस्था की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2017 देश भर के 32 राज्य संसाधन केन्द्रों एवं लगभग 300 जन शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन 'सैंटर फॉर मार्केट रिसर्च एण्ड सोशल डिवलैपमैंट' से करवाया। मूल्यांकन करने वाली संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य संसाधन केन्द्रों को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के रूप

में विकसित किया जाए। इनके अनुदान को बढ़ाया जाए। यहां पर बहुत ही अनुभवी व प्रौढ़ मनोविज्ञान की समझ रखने वाला स्टाफ है। हालांकि जन शिक्षणसंस्थानों के बारे में भी रिपोर्ट अच्छी थी। लेकिन साक्षरता अभियान में राज्य संसाधन केन्द्रों की भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है।

लेकिन हैरानी की बात है कि संसद में पिछले दरवाजे 'राज्य सभा' से प्रवेश पाने वाले मानव संसाधन विकास मत्री प्रकाश जावड़ेकर और उनकी मुंह लगी स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार की सचिव, आईएएस अधिकारी रीना राय ने साक्षर भारत अभियान का भटठा बैठा दिया। राज्य संसाधन केन्द्रों की आर्थिक मदद रोक दी। साक्षर भारत अभियान को बन्द कर दिया। सरकारी आंकड़े के अनुसार देश के 25 करोड़ अनपढ़ों, गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 50 करोड़ असाक्षरों के जीवन में शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के मौके को छीन लिया।

मूल्यांकन एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मंत्रालय द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को राज्य संसाधन केन्द्र बहुत बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। संसाधन केन्द्रों द्वारा छापी गई शिक्षण सामग्री को बहुत ही उम्दा बताया गया। बहुत ही योग्य और अनुभव स्टाफ इनमें कार्यरत है। इन संस्थानों और ज्यादा मजबूत करने के सुझाव दिए गए। साथ ही मूल्यांकन एजेंसियों ने इनकी आर्थिक मदद बढ़ाने के साथ-साथ कुछ और भी सुझाव दिये।

यह सब जानकारी सूचना अधिकार कानून के तहत मिली है।

लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है 2017 महानिदेशक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, भारत सरकार, सुश्री रीनाराय एवं उनके कुछ लग्गे-भग्गे अधिकाारियों ने भारत सरकार की मूल्यांकन एजेंसियों की रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यही नहीं देश भर में स्थित राज्य संसाधन केन्द्रों की वित्तीय मदद को रोक दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वे भी इस साजिश में शामिल हो गये। राज्य संसाधनों का भटठा बैठाने वाली आई ए एस अधिकारी सुश्री रीना आज भी भारत सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग में शिक्षा सचिव के पद पर शिक्षा का भटठा बैठाने के लिए जमी हुई हैं।

प्रकाश जावड़ेकर का अपना धंधा भी है

सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी मिली है कि प्रकाश जावड़ेकर ने व्यक्तिगत रुचि लेकर देश में चल रहे 150 करोड़ से अधिक सालाना बजट वाले जन शिक्षण संस्थानों को कौशल विकास मंत्रालय से जोड़ने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कौशल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को जावड़ेकर ने जन शिक्षण संस्थानों को उनके मंत्रालय से जोड़ने के लिए राजी किया।

बताया जाता है कि जावड़ेकर की जन शिक्षण संस्थानों को कौशल विकास से जोडने में व्यक्तिगत रूचि लेने का मुख्य कारण यह है कि उनके भी अपने जन शिक्षण संस्थान हैं। उनकी मुंह लगी आईएएस अधिकारी स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार की सचिव रीना राय और जावड़ेकर के निजी स्वार्थों की वजह से 25 करोड़ सालाना बजट वाले 32 राज्य संसाधन केन्दों का बजट बन्द करके इनके योग्य, कर्मठ और 30-30 साल के तुजुर्बेकार एवं प्रौढ़ मनोविज्ञान में दक्ष व्यक्तियों को सड़क पर ला दिया है।

सालाना 150 करोड़ के बजट वाले जन शिक्षण संस्थानों को भी कौशल विकास एवं उद्यमीयता मंत्रालय के जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी यह कौशिश सफल हो गई लगता है। जावड़ेकर साहब जन शिक्षण संस्थानों को कौशल विकास मंत्रालय में जोड़ने के लिए इतने ज्यादा प्रयासरत क्यों है?

कारण साफ है, कांग्रेस के राज में उन्होंने भी जन शिक्षण संस्थाएं लिए थे। दूसरी और देखा जाए तो राज्य संसाधन केन्द्रों का बजट केवल 25 करोड़ सालाना है। साथ इनमें जन शिक्षण संस्थानों मुकाबले शैक्षणिक रूप से ज्यादा बेहतर स्टाफ है।

क्या है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

देश में साक्षरता अभियानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण' की स्थापना की गई थी। इसके अलावा राज्य स्तर पर 'राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण' इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते हैं।

राज्य संसाधन केन्द्र पिछले 28-30 वर्षों से प्रौढ़ मनोविज्ञान के अध्ययनों और शिक्षाशास्त्र के आधार पर साक्षरता अभियान के लिए एक सहयोगी संस्थान के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों सहित स्वयंसेवियों के प्रशिक्षण, पठन-पाठन सामग्री एवं नवसाक्षर साहित्य तैयार करने और साक्षरता के पक्ष में वातावरण बनाने में इस संस्थान की अहम् भूमिका है। अपने लम्बे अनुभव के आधार पर राज्य संसाधन केन्द्रों ने सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता की भाषा और बोलियों में ग्राम स्तर तक प्रभावी तरीके से ले जा कर साक्षरता अभियान को गति देने का कार्य किया है। राज्य संसाधन केन्द्रों को लम्बे समय से इस तरह के काम करने के लिए ही प्रशिक्षित किया गया है। इन संसाधन केन्द्रों को विकसित करने में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, भारत सरकार के अधिकारियों तथा देश-विदेश के शिक्षाविदों एवं प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञों ने बेहद ऊर्जा एवं बौद्धिक श्रम लगाया है। इसी की परिणाम है कि इन केन्द्रों में कार्यरत लगभग 500 कर्मचारी निरक्षरों, स्वयंसेवी अध्यापकों एवं युवा कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित करने, उन्हें प्रशिक्षण देने, धरातल से राजय स्तर तक मॉनीटरिंग करने तथा विशेष तौर पर प्रौढ़ मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण-प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार करने में सक्षम हुए हैं।

राज्य संसाधन केन्द्र (एस.आर.सी.) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित संस्थान है। देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत 32 राज्य संसाधन केन्द्र, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार एवं समय-समय पर भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार अपने-अपने राज्यों में राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत स्तर पर साक्षरता, शिक्षा एवं विकासात्मक कार्यों में अकादमिक एवं तकनीकी योगदान प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा विशेष तौर पर प्रौढ़ नवसाक्षरों के लिए 10 हजार से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन करने के साथ-साथ राज्य विशेष की जरूरतों के अनुसार विभिन्न भाषाओं में पाठ्यक्रम, प्राइमर तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं।

राज्य संसाधन केन्द्रों में लगभग 500 अनुभवी, प्रशिक्षित मानव संसाधन कार्यरत हैं। अर्थात 500 परिवार इन केन्द्रों से जुड़े हैं। देश अलग-अलग राज्यों में स्थापित 32 राज्य संसाधन केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा केवल 25 करोड़ रूपए वार्षिक अनुदान दिया जाता है, जो इस महत्वपूर्ण कार्य की संगति में बहुत बड़ी राशि नहीं है।

राज्य संसाधन केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। प्रत्येक राज्य संसाधन केन्द्र की रचनात्मक गतिविधियों हेतु स्वशासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। इनके मार्गदर्शन में रचनात्मक गतिविधियों का संपादन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में राज्य संसाधन केन्द्रों की एकरूपता हेतु इनका अलग से पंजीयन भी कराया गया।

राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता कार्यक्रम की रीढ़ हैं, जिनके बिना इस कार्यक्रम के संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पिछले लगभग 28 सालों में इन केन्द्रों ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महारत हासिल की है और देश में प्रौढ़ शिक्षा की परिकल्पना को जमीन पर उतारने का आधार प्रदान किया है। देश का कोई भी प्रशिक्षण एवं अकादमिक संस्थान इनकी प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता। इसके बावजूद वर्तमान में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकारण के कुछ अधिकारी इनकी भूमिका और महत्व को समझे बिना इन्हें दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06